web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 25 फरवरी 2025 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 148

अंर्राष्ट्रीय

फ्रांस में रूसी वाणिज्य दूतावास के पास धमाका, इलाके में मचा हड़कंप

मॉस्को/मार्सिले । फ्रांसीसी शहर मार्सिले में रूसी वाणिज्य दूतावास में सोमवार को विस्फोट हुआ। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूतावास के परिसर में हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने सरकारी समाचार एजेंसी तास से कहा, मार्सिले में रूसी महावाणिज्य दूतावास के क्षेत्र में हुए विस्फोटों में आतंकवादी हमले के सभी लक्षण हैं। हम मांग करते हैं कि जांच के लिए व्यापक और त्वरित कदम उठाए जाएं, साथ ही रूसी विदेशी मिशनों की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। फ्रांसीसी और रूसी मीडिया की रिपोर्टों से पता चला है कि विस्फोट सोमवार मार्सिले में रूसी वाणिज्य दूतावास के पास हुआ, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांसीसी समाचार चैनल बीएफएमटीवी के हवाले से तास ने बताया कि लगभग 30 अग्निशमन और बचाव कर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया। बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने वाणिज्य दूतावास के बगीचे में दो आग लगाने वाले उपकरण फेंके। विस्फोट स्थल के पास एक चोरी की गई कार भी मिली, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गईं। यह विस्फोट रूस और पश्चिम में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, खासकर यूरोपीय संघ की ओर से मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों के अपने 16वें पैकेज की घोषणा के बाद। यह घटना यूक्रेन-रूस युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर हुई। बता दें 22 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमान का सैन्य आक्रमण किया था। पिछले सप्ताह, रूस की विदेशी खुफिया सेवा (एसवीआर) ने दावा किया था कि यूक्रेनी अधिकारी कथित तौर पर जर्मनी, बाल्टिक राज्यों और स्कैंडिनेविया सहित यूरोप में रूसी राजनयिक मिशनों पर हमले की योजना बना रहे थे।

ट्रंप के फैसले ने मचाई खलबली, यूएसएआईडी के 1600 कर्मचारियों को निकाला

वाशिंगटन । डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के 1,600 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अतिरिक्त कर्मचारियों को सवेतन प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया। इस कदम की पुष्टि प्रशासक कार्यालय की ओर से यूएसएआईडी कर्मचारियों को भेजे गए एक कम्युनिकेशन के माध्यम से की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला कई कानूनी चुनौतियों के बाद लिया। ट्रंप प्रशासन को हजारों यूएसएआईडी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कोशिश के दौरान कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने शुरुआत में एजेंसी को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन एक फेडरल जज ने कानूनी मुश्किलें खड़ी कर दीं और अस्थायी रूप से ऐसी कार्रवाइयों को रोक दिया। हालांकि, शुक्रवार को आए एक फैसले ने रोक हटा दी, जिससे मौजूदा छंटनी जारी रखने का रास्ता साफ हो गया। बयान में निर्दिष्ट किया गया कि महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर्मचारी अप्रभावित रहेंगे, हालांकि ऐसे कर्मचारियों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया गया।

भारी बर्फबारी के कारण तुर्की के 18 प्रांतों में 2,173 सडक़ें अवरुद्ध, जनजीवन अस्त-व्यस्त

अंकारा । भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफानों ने तुर्की के 18 प्रांतों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। टीआरटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2,173 सडक़ें बंद हो गई हैं। पूर्वी वान प्रांत के महानगरीय क्षेत्र में 19 इलाकों और 35 छोटे गांवों का संपर्क टूट गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, एरसिस जिले में बर्फ की मोटाई 40 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है, जहां सडक़ें साफ करने का काम जारी है। पूर्वी मुस प्रांत में प्रशासन बर्फबारी से लोगों को होने वाली परेशानी कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन अब भी 46 गांवों की सडक़ें बंद हैं। दक्षिण पूर्वी बिटलिस प्रांत में भी हालात गंभीर हैं। यहां 50 गांवों की सडक़ें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं। पूर्वी हक्कारी में शुक्रवार को भारी बर्फबारी के कारण 34 बस्तियों का संपर्क कट गया था, जिनमें से 32 को फिर से जोड़ दिया गया है। हालांकि, शेमदीनली ज़िले के एलन गांव और युकसेकोवा ज़िले के अक्टोपरेक छोटे गांव में हिमस्खलन के खतरे के कारण रास्ते खोलने का काम नहीं हो सका है। काला सागर क्षेत्र में ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी का अधिक असर पड़ा है।

छत्तीसगढ़ का बजट : 24 बरस में 5700 से डेढ़ लाख करोड़ पहुंचा, छह बरस पहले हुआ लखटकिया

रायपुर । आरएनएस

मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल से अधिक हो गए। इस साल वार्षिक बजट का आकार पौने दो लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है यानी करीब 30 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। जाहिर है, आने वाले साल में बजट लगभग दो लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। मूल बजट के अलावा हर साल अनुपूरक बजट भी पेश होते रहे हैं, इसलिए सालाना आंकड़ा तेजी से उछले। राज्य बनने के बाद बजट 5700 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजीत जोगी के नेतृत्व में राज्य की पहली सरकार बनी थी। तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के बजट का इतिहास दिलचस्प रहा है।

छत्तीसगढ़ के ज्यादातर बजट मुख्यमंत्री ने ही पेश किए हैं। छत्तीसगढ़ के इन 25 सालों के इतिहास पर एक नजर डालें, तो कोरिया राजघराने से तालुक रखने वाले स्व. डॉ. रामचंद्र सिंहदेव राज्य के पहले वित्त मंत्री थे। इन्होंने बतौर वित्त मंत्री 3 बार छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया था। रामचंद्र सिंहदेव ने 2001-02 में कुल 7 हजार 294 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। 2002-03 तक में 8 हजार 471 करोड़ के आम बजट के साथ एक अनुपूरक बजट पेश किया था। 2003-04 तक में 9 हजार 978 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साथ ही दो अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। उसके बाद भाजपा सरकार आने पर 15 साल तक बजट के आकार में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। फिर 2019-20 से कांग्रेस सरकार पे पांच साल बजट पेश किया।

रमन ने 12 बार - 2007 में रमन सिंह ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। 2007 से लेकर 2018 तक रमन सिंह ने वित्त विभाग को अपने पास रखा और हर साल बतौर सीएम वे बजट पेश करते रहे। इस तरह रमन सिंह ने कुल 12 बार बजट पेश किया। 2018-19 में अंतिम बजट पूश किया। उनके कार्यकाल के दौरान बजट में मूल रुप से अधोसंरचना विकास पर फोकस रहा।

वर्ष	बजट राशि	वर्ष	बजट राशि
2001-02	7 हजार 294 करोड़	2013-14	44 हजार 169 करोड़
2002-03	8 हजार 471 करोड़	2014-15	54 हजार 710 करोड़
2003-04	9 हजार 978 करोड़	2015-16	65 हजार 013 करोड़
2004-05	10 हजार 555 करोड़	2016-17	76 हजार 032 करोड़
2005-06	11 हजार 242 करोड़	2017-18	88 हजार 599 करोड़
2006-07	13 हजार 185 करोड़	2018-19	95 हजार 899 करोड़
2007-08	16 हजार 473 करोड़	2019-20	1 लाख 20 हजार करोड़
2008-09	19 हजार 392 करोड़	2021-22	97 हजार 106 करोड़
2009-10	23 हजार 482 करोड़	2022-23	1 लाख 04 हजार 603 करोड़
2010-11	26 हजार 099 करोड़	2023-24	1 लाख 21 हजार 501 करोड़
2011-12	32 हजार 477 करोड़	2024-25	1 लाख 47 हजार 446 करोड़
2012-13	39 हजार 677 करोड़		

कोटा में जिंदगी और मौत के बीच फंसा सिस्टम : ट्रैफिक जाम में फंसे 3 साल के मासूम की मौत, समय पर अस्पताल नहीं ले जा सके परिजन

कोटा । आरएनएस

कोटा में ट्रैफिक जाम सिर्फ गाडिय़ों को ही नहीं, बल्कि अब ज़िंदगियों को भी रोकने लगा है! 3 साल के मासूम हरिओम की जान चली गई, लेकिन सिंगल लेन वाली यह सडक़ अपनी सुस्त चाल से टस से मस नहीं हुई। माता-पिता हॉस्पिटल जाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन जाम को कोई जल्दी नहीं थी—वो आराम से पसरा रहा, मानो 'कछुआ गति' का स्वर्णिम युग वापस आ गया हो!

अब आप ही सोचिए—हाईवे पर जाम हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के "निर्देश" जारी होते हैं, अस्थायी डिवाइडर लगाए जाते हैं, पुलिस चौकी बनाई जाती है... और फिर भी जाम ऐसा अड़ा रहता है कि वो खुद किसी 'वीआईपी' से कम नहीं लगता! शायद यही वजह है कि सिस्टम से ज्यादा यहां ट्रैफिक की पकड़ मजबूत है।

वैसे, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाली यह सडक़ असल में "ट्रैफिक रिजर्व" बन गई है। प्रशासन को शायद इस बात की उम्मीद थी कि गाडिय़ां और लोग खुद ही जंगल का रास्ता पकड़ लेंगे, लेकिन अफसोस... बाघों के इलाके में इंसान फंसे हुए हैं और इंसानों की बनाई व्यवस्था जंगलराज में तब्दील हो चुकी है।

15 दिन पहले भी एक और जान चली गई थी, लेकिन किसी ने सबक लिया? नहीं! अब अगली मौत का इंतजार है, ताकि नए सिरे से 'निंदा', 'जांच समिति' और 'निर्देश' का ड्रामा दोहराया जा सके।

कोटा वालों, खुद ही अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि इस जाम में किसी को बचाने का समय नहीं है—न प्रशासन के पास, न नेताओं के पास, और न ही उस 'सडक़' के पास, जो खुद बेबस होकर तमाशा देख रही है!

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 6 मंत्रियों ने विधानसभा सदस्य के रूप में ली शपथ

नई दिल्ली । आरएनएस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसभा का पहला सत्र सोमवार सुबह शुरू हुआ और सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंदर सिंह इंद्राज, पंकज कुमार सिंह और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी शपथ ली। विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी (आप) के 22 विधायकों ने भी पहले सत्र के दौरान शपथ ली।

इससे पहले भाजपा के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गांधी नगर के विधायक को राज निवास में शपथ दिलाई। अरविंदर सिंह चार बार विधायक रह चुके हैं। वह नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे।

दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र तीन दिनों तक चलेगा। सत्र की शुरुआत भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेकर की। उपराज्यपाल (एल-जी) विनय कुमार सक्सेना ने राज निवास पर लवली को शपथ दिलाई।

विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव दोपहर 2 बजे होगा। विधानसभा बुलेटिन के अनुसार, उपराज्यपाल सक्सेना 25 फरवरी को सदन को संबोधित करेंगे। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की जाएगी।

बता दें कि रेखा गुप्ता ने गुरुवार को रामलीला मैदान में एक बड़े समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। रेखा गुप्ता, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। वह मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी भाजपा नेता हैं।

दर्दनाक हादसा : तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 की मौके पर मौत; कई घायल

पटना । आरएनएस

बिहार के पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात एक ट्रक ने यात्रियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई। कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस के अनुसार, देर रात मसौढ़ी थाना अंतर्गत स्थित नूरा पुल के पास एक ट्रक और एक ऑटो के बीच टक्कर होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौढ़ी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां सात व्यक्तियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है।

बताया गया कि बालू लदे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो सवार सात लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक ऑटो के पूरी तरह ऊपर आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में सभी मजदूर बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि पटना से मजदूरी करके ये सभी तारेगना स्टेशन पर उतरे थे और फिर वहां से ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। इस बीच पितवांस की ओर से जा रहे एक बालू लदे ट्रक से ऑटो की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहन सडक़ किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नजदीक के गांव से प्रत्येक दिन लोग मजदूरी करने के लिए पटना जाते थे और काम करके देर रात अपने घर लौट आते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पेड़ से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़कर बस से जा भिड़ी एसयूवी कार, 6 की मौत-2 घायल

जबलपुर (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के खितौली थाना क्षेत्र के पहरेवा इलाके में सोमवार तडक़े भीषण सडक़ हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज से जबलपुर जा रही एसयूवी गाड़ी पहले पेड़ से टकराई और फिर डिवाइडर तोड़ते हुए रॉंग साइड पर पहुंच गई। इस दौरान दूसरी तरफ से एक बस जबलपुर से कटनी जा रही थी दोनों गाडिय़ों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सडक़ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहंची और सबसे पहले ट्रैफिक को चालू किया गया। मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया वहीं 2 घायलों को सिहोरा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। मृतकों की पहचान विरुपक्सि गुमती, बस्वराज कुरति, बालाचंद्र और राजू के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान सदाशिव और मुस्ताफ के रूप में हुई है।

संभल की जामा मस्जिद सरकार की जमीन पर बनी, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली । आरएनएस

उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यूपी सरकार ने कहा- संभल की शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। मस्जिद के पास मौजूद कुआं भी सरकारी जमीन पर है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 'ऐसा होना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा।

मस्जिद समिति का आवेदन कुएं की पुनरुद्धार प्रक्रिया को ना सिर्फ नाकामयाब करने की कोशिश है, बल्कि यह क्षेत्र के संरक्षण, विकास एवं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, जैसा कि सुनवाई के दौरान किया गया था।' कुआं उन 19 कुओं का हिस्सा है जो जिला प्रशासन की ओर से पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। बारिश के पानी का संचयन और जल पुनर्भरण के बाद सभी समुदायों की ओर से उपयोग किया जा सकेगा। इन प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है. सांस्कृतिक रूप से भी संभल में पर्यटन को आकर्षित करेगा।

दुनिया को भारत से बहुत आशाएं : भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में बोले पीएम मोदी

भोपाल । आरएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है।

राजधानी के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में चाहे जन सामान्य हो या नीति के जानकार, या देश अथवा संस्थान, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले कुछ समय में जो कमेंट्स आए हैं, वे भारत में हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश बना रहेगा। क्लाइमेट चेंज की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर का सुपर पावर कहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल एयरोस्पेस के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के तौर पर उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजिंग का जवाब वे भारत में देख रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। यह कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और आज यह मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी महसूस किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का पांचवा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश कृषि के मामले में भारत के प्रमुख राज्यों में है। खनिज के हिसाब से भी मध्य प्रदेश देश के पांच प्रमुख राज्यों में से है। मध्य प्रदेश को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते दो दशकों में मध्य प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा गया है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सी दिक्कत थी, कानून-व्यवस्था की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालात में यहां इंडस्ट्रीज का विकास बहुत मुश्किल था। बीते दो दशकों में मध्य प्रदेश के लोगों के सहयोग से यहां की भाजपा सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया।

पीएम मोदी ने आगे कहा, दो दशक पहले तक लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, आज मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों में टॉप के राज्यों में स्थान बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जिस मध्य प्रदेश में कभी सडक़ों के कारण बसे तक नहीं चल पाती थीं, वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत के लीड राज्यों में से एक है। जनवरी 2025 तक दो लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। मध्य प्रदेश आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए सेक्टर के रूप में एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। बीते दशक में भारत ने अधोसंरचना का दौर देखा है। कहा जा सकता है इसका बहुत फायदा मध्य प्रदेश को मिला। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से ही होकर गुजरता है। एक तरफ मध्य प्रदेश को मुंबई के पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी मिल रही है, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी जोड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में पांच लाख किलोमीटर से अधिक तक का रोड नेटवर्क है।